



दैनिक फ़ाइट अगस्त क्रिमिनल



वर्ष : ०८ अंक : ३०८ मुंबई, बुधवार ०२ अप्रैल २०२५ RNI No. : MAHHIN/2016/71734 पृष्ठ-४ मूल्य २/रु.

अजित दादा का 100 करोड़ का वादा, चाचा के विधायकों के साथ बैठक का दौर, संपर्क में कौन, क्या ऑफर?.....

मुंबई: लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद महायुति ने विधानसभा चुनाव में वापसी की। उन्होंने 237 सीटें जीतीं। वहीं महाविकास अघाड़ी को करारी हार मिली और



उन्हें 50 सीटें भी नहीं मिलीं। विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष का प्रभाव कम दिखा। NCP के अध्यक्ष शरद

पवार अभी सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। वहीं जयंत पाटील के 'डू' में जाने की चर्चा है। शरद पवार के कई विधायक अजित पवार की 'ग' के संपर्क में हैं। अजित पवार विकास के मुद्दे पर महायुति के साथ गए थे। अब वे शरद पवार के विधायकों को भी इसी मुद्दे पर अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अजित पवार उन्हें विकास के लिए फंड का वादा दे रहे हैं। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' की खबर के अनुसार, अजित पवार शरद पवार के विधायकों को 'ग' में शामिल होने का प्रस्ताव दे रहे हैं। वे उन्हें उनके क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर फंड देने का वादा कर रहे हैं। शरद पवार के पास विधानसभा में केवल 10 विधायक हैं। अगर अजित पवार को दल-बदल कानून से बचना है, तो उन्हें 7 विधायकों को अपने साथ लाना होगा। अजित पवार का ध्यान सोलापुर पर है। सोलापुर ने शरद पवार को 4 विधायक दिए हैं। ये विधायक हैं: अभिजीत पाटील (माढा), राजू खरे (मोहोळ), उत्तम जानकर (माळशिरस), और नारायण पाटील (करमाळा)। ये सभी तुलारी चुनाव चिन्ह पर जीते हैं। अजित पवार इन विधायकों पर खास ध्यान दे रहे हैं।

पहले मस्जिद में ब्लास्ट फिर मंदिर में इस्लामिक झंडा, नागपुर के बाद एक और जिले को सुलगाने की साजिश!

महाराष्ट्र के बीड से एक बड़ी खबर सामने आई है। कट्टरपंथियों ने बीड के हिंदू मंदिर में इस्लामिक झंडा लगा दिया। इससे इलाके में तनाव फैल गया है। फिलहाल पुलिस ने मंदिर से झंडे को उतरवा दिया है। हालांकि किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि ईद से एक दिन पहले ही बीड में ही मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। महाराष्ट्र के बीड जिले में हुए मस्जिद ब्लास्ट मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस केस की जांच अब महाराष्ट्र 'एड' कर रही है। फिलहाल ब्लास्ट के लिए जिलेटिन कहां से लाई गई तथा इसके पीछे कौन लोग हैं? एटीएस इस बात की जांच में जुट गई है। जिन आरोपियों की गिरफ्तार की गई है, उनकी पहचान विजय राम गहाणे (22) तथा श्रीराम अशोक सागडे (24) के रूप में हुई है। बीड पुलिस ने विस्फोट के महज 3 घंटे के भीतर इन आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से जिलेटिन इस्तेमाल करने के किसी भी प्रकार के कोई लाइसेंस नहीं हैं।

इसी बीच महाराष्ट्र के बीड जिले में ही एक गांव में मंदिर पर हरे रंग का झंडा लगाए जाने से इलाके में कुछ वक्त के लिए तनाव पैदा हो गया। बाद में पुलिस ने सोमवार को दो अलग-अलग समुदायों के स्थानीय निवासियों से बात की तथा स्थिति को नियंत्रण में किया।

10 साल बाद भी ट्रैफिक जाम, कचरे के ढेर और जलभराव, कहां है स्मार्ट सिटी?

स्मार्ट सिटी या धोखा? मुलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है भारत



■ **सईद शेख**
नई दिल्ली। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने देश के 100 शहरों को 'स्मार्ट' बनाने के लक्ष्य के साथ एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यह दावा किया गया था कि इन शहरों को डिजिटल तकनीकों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और टिकाऊ विकास से लैस किया जाएगा, जिससे नागरिकों का जीवन अधिक सुविधाजनक और आधुनिक हो जाएगा। लेकिन आज, जब इस योजना को दस साल पूरे हो चुके हैं, तो सवाल उठता है—क्या यह मिशन अपने उद्देश्यों को पूरा कर सका है, या फिर यह सिर्फ एक और अधूरी सरकारी योजना बनकर रह गया? सरकार ने इस योजना के तहत शहरों को ट्रैफिक प्रबंधन, कचरा निपटान, जल आपूर्ति, स्वच्छता और डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर बनाने का दावा किया था। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी अधिकतर शहर उन्हीं समस्याओं से

जूझ रहे हैं, जो 2015 में थीं। स्मार्ट ट्रैफिक लाइट लगाने का वादा किया गया था, लेकिन दिल्ली, मुंबई, कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में जाम की स्थिति बदतर हो गई है। स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर नागरिकों में नाराज़गी बढ़ रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ इमारतें खड़ी कर दी गईं, लेकिन उनकी रोजमर्रा की समस्याओं का हल नहीं निकाला गया। सड़कें खराब हैं, पेयजल संकट जारी है और बिजली कटौती आम बात बनी हुई है। अगर सरकार वाकई स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है, तो उसे पहले बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। केवल डिजिटल सेवाओं और सीसीटीवी कैमरों से कोई शहर स्मार्ट नहीं बन सकता। पारदर्शिता, जवाबदेही और ठोस कार्ययोजना के बिना यह मिशन बस एक और असफल सरकारी योजना बनकर रह जाएगा।

कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि एक और जुमले का अंत हुआ। सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को बंद कर दिया है। सौ स्मार्ट सिटी पर होनेवाला था काम, 10 साल में तीन बार बढ़ाई गयी डेडलाइन, 84 सीटी में 14 हजार करोड़ का काम अभी भी अधर में लटका हुआ है।



जलभराव और प्रदूषण

मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहर आज भी बारिश में डूब जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की योजनाएं या तो धीमी हैं या पूरी तरह से विफल रहतीं। दिल्ली, गाजियाबाद, वाराणसी और पटना में प्रदूषण की स्थिति पहले से अधिक खराब हुई है। स्मार्ट सिटी बनने के बाद भी इन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में बना रहता है।

कचरा प्रबंधन की असफलता

स्वच्छता के नाम पर कुछ शहरों में कचरा प्रसंस्करण संयंत्र लगाए गए, लेकिन इनमें से अधिकतर आज भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे। वाराणसी, मेरठ, कानपुर और गुवाहाटी जैसे शहरों में कचरे के ढेर आज भी आम नज़ारा हैं।

अधुरी परियोजनाएँ और भ्रष्टाचार के आरोप

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जिन शहरों का चयन हुआ, वहां करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन अधिकतर परियोजनाएँ अब भी अधूरी हैं। कई शहरों में

सड़कें खुदी पड़ी हैं, स्मार्ट बस स्टॉप केवल कागज़ों पर हैं और डिजिटल प्रशासन प्रणाली पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है। कई मामलों में सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, जिससे इन परियोजनाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं।

कौन-कौन से शहर वाकई स्मार्ट बने?

कुछ गिने-चुने शहर जैसे इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद और पुणे ने सफाई और डिजिटल सेवाओं में सुधार किया है, लेकिन इनकी संख्या बेहद कम है। दूसरी ओर, बनारस, पटना, जयपुर, मेरठ, कोच्चि और कोलकाता जैसे शहरों में कोई ठोस बदलाव नहीं दिखता।

क्या सरकार की योजना विफल हो गई?

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को एक दिखावटी परियोजना की तरह चलाया। योजनाओं को पूरा करने की कोई ठोस समय-सीमा तय नहीं की गई, निगरानी व्यवस्था कमजोर रही और नागरिकों की वास्तविक ज़रूरतों को नजरअंदाज किया गया।

बाबा के बुलडोजर पर 'सुप्रीम' एक्शन, 6 सप्ताह के अंदर देना होगा 10-10 लाख का मुआवजा, अखिलेश यादव ने कुरेदा जख्म!

लखनऊ: यूपी के प्रयागराज में बिना नोटिस दिए बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पीड़ितों को दस-दस लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट का आदेश आते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैंसले का स्वागत किया और यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अंबेडकरनगर की घटना का भी जिक्र किया जिसमें बुलडोजर से झोपड़ी गिराई जा रही है और एक लड़की अपनी किताबें बचाने के लिए भाग रही है। अखिलेश ने उसी लड़की का वीडियो एक्स पर शेयर किया और कहा कि घर एक भावना का नाम है। इसके टूटने से भावनाएं आहत होती हैं।

और क्या कुछ बोले अखिलेश?: अखिलेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट

का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण 2021 में



प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को 6 सप्ताह में 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देना। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने

के 24 घंटे के भीतर घर गिराने की कार्रवाई को अवैध करार दिया है।

घर सिर्फ पैसों से नहीं बनता: सपा मुखिया अखिलेश ने कहा कि सच तो यह है कि घर सिर्फ पैसों से नहीं बनता और न ही उसके टूटने का दर्द सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार के लिए घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती हैं, उनकी भरपाई न तो की जा सकती है और न ही कोई उन्हें पूरी तरह से पूरा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण की खिंचाई की और प्रयागराज में घरों को गिराने की कार्रवाई को 'अमानवीय और गैरकानूनी' बताया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि घरों को गिराने की कार्रवाई 'अनुचित' तरीके से की गई।

वक्त बिल के सपोर्ट में आए नीतीश-नायडू, जेडीयू ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, जगदंबिका पाल बोले- विरोध के लिए कुछ नहीं

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार यानी 2 अप्रैल को संसद में वक्त संशोधन विधेयक पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर भाजपा ने भी अपने सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। भाजपा का अनुसरण करते हुए नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है।

वक्त विधेयक पर राजनीति भी चरम पर है। विपक्षी सांसद रणनीतिक चालें चल रहे हैं और इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ लामबंद विपक्षी नेता इस मुद्दे पर एनडीए के सहयोगी दल जदयू और टीडीपी को भड़काना चाहते हैं। लेकिन इस बीच टीडीपी और जदयू ने अपनी सहमति दे दी है। दोनों ने व्हिप जारी किया है।

किरेन रिजिजू ने किया बड़ा दावा उधर, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया कि विधेयक के पक्ष में न सिर्फ एनडीए एकजुट है, बल्कि विपक्षी भारत गठबंधन के कई सांसदों ने भी इसका समर्थन किया है। रिजिजू ने कहा कि कई विपक्षी सांसदों ने विधेयक को जल्द लाने की मांग की है।

क्या बोले जेपीसी चीफ जगदंबिका पाल
वहीं, वक्त बिल को लेकर गठित जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने भी चंद्रबाबू नायडू की तेलगू देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के समर्थन की पुष्टि की है। इससे पहले खबरें थी की जेडीयू और टीडीपी वक्त बिल के पक्ष में नहीं हैं। पाल ने यह भी कहा कि

विपक्ष के पास बिल का विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है।



क्यों लग रहे थे 'धोखे' के कयास
जदयू के लतन सिंह ने कहा था कि हम संसद में इस बिल पर अपना रुख साफ करेंगे। वहीं, संजय झा ने एक बयान में

कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति जब तक है तब तक लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। इन दोनों नेताओं के बयान को भी केन्द्र की मोदी सरकार को इशारा माना गया। जिसके बाद कयास थे कि दोनों ही पार्टियों के सांसद बिल के खिलाफ वोट कर सकते हैं।

निर्णायक भूमिका में जेडीयू-टीडीपी
जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसद बिल के पक्ष या विपक्ष में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दोनों ही पार्टियां अपने-अपने राज्यों में मुस्लिम वोटों पर भी निर्भर हैं, जिसके चलते वे सत्कर्ता बरत रही हैं। ये पार्टियां सरकार के साथ रहेंगी या मुस्लिम भावनाओं को तरजीह देंगी, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।

SHABBIR MEMON (DIRECTOR) 9892488825. TEL: 022 6780894

MEMON REALTORS

Builder & Developer PVT. LTD.

Shop No. 1 to 5, Bldg. No. 2 Next Ahuja Bulding R.M. Road, Oshiwara, Jogeshwari(W), Mumbai - 400 102. memonshabbir24@gmail.com

संपादकीय



भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप

दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही महीनों के कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा चर्चित और विवादाित राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के पहले उन्होंने, जिस तरह से दुनिया के सभी देशों को ट्रंप को लेकर धमकाना शुरू कर दिया था। यूरोपीयन एवं नाटो देशों

को ट्रंप एवं सुरक्षा समझौतों को लेकर जिस तरह के अनाप-शनाप बयान और धमकी दी है। उससे अमेरिका के यूरोपीय देशों के साथ-साथ सारी दुनिया के देशों में एक नई अफरा तफरी मची हुई है। सारी दुनिया के देशों में आर्थिक मंदी के साथ-साथ ट्रंप युद्ध को लेकर नया तनाव देखने को मिल रहा है। ट्रंप के सलाहकार एलन मस्क उनसे एक कदम आगे चल रहे हैं। अमेरिका में लाखों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। अप्रवासी नीति को लेकर अमेरिका के राज्यों के साथ ट्रंप के मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने लैंगिक पहचान और महिला अधिकारों पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा औरत वह होती है, जो बच्चा पैदा कर सकती है। ट्रंपसजेंडर को लेकर पहले भी उनके आपत्तिजनक बयान आए थे। अब उन्होंने सीधे-सीधे उन महिलाओं को महिला मानने से इनकार कर दिया है। जो मां बनने में सक्षम नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही के निर्णयों में महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। न्यू जर्सी के एक कार्यक्रम में महिला पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जो महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। जो महिला पुरुषों से ज्यादा स्मार्ट है। जो पुरुषों की सफलता में बाधा बनती है। इस तरह के विवादाित बयान देकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को ईश्वर के समकक्ष अपने आपको खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है, वह 2029 में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए संविधान बदलना होगा, तो वह बदल देंगे। ट्रंप, सारी दुनिया के देशों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उसकी विभिन्न प्रतिक्रिया सारी दुनिया के देशों में हो रही है। अमेरिका के अंदर भी उनकी लोकप्रियता में दो माह के अंदर सात फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। इतने कम समय में लोकप्रियता में इतनी बड़ी गिरावट किसी भी राष्ट्रपति के बारे में इसके पूर्व देखने को नहीं मिली। इसके बाद भी ट्रंप और एलन मस्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। एलन मस्क के निर्णयों के खिलाफ सारे अमेरिका में 227 से ज्यादा स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। एलन मस्क की गाड़ियों को जलाया जा रहा है। उनकी कंपनियों के शेयर अमेरिकी नागरिकों द्वारा बेचे जा रहे हैं। अमेरिका के विभिन्न राज्यों की न्यायापालिका ने ट्रंप के कई प्रशासनिक आदेशों के पालन पर रोक लगा दी है। ट्रंप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उसको देखते हुए अमेरिका और बाहर के देशों में उनकी छवि एक मूर्ख, लालची या अहंकारी नेता के रूप में बन रही है। अमेरिका जैसे देश में इसके पहले कोई भी राष्ट्रपति इस तरह से विवादाित नहीं रहा।

टैक्सी और ऑटो चालकों पर बढ़ेगा संकट; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ई-बाइक टैक्सी को दिखाएंगे हरी झंडी

सिंगल यात्री को सुविधा, ऑटो-टैक्सी के धंधे पर पड़ेगा

मुम्ना मुजावर
राज्य सरकार ने ई-बाइक टैक्सियों को अनुमति देने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। यह



प्रस्ताव आज परिवहन विभाग द्वारा कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया गया। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में हुई इस बैठक में महाराष्ट्र में सिर्फ ई-बाइक टैक्सियों को ही अनुमति देने का फैसला किया गया।

ई-बाइक टैक्सियों के संबंध में वास्तव में क्या निर्णय लिया गया है?

प्रताप सरनाईक ने महाराष्ट्र में शीघ्र ही लागू की जाने वाली ई-बाइक टैक्सी पहल के बारे में जानकारी दी। प्रताप

सरनाईक ने कहा, 'ई-बाइक टैक्सी का प्रस्ताव परिवहन विभाग के माध्यम से कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया था। सभी मंत्रियों ने महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी को अनुमति दे दी है। अभी तक अकेले यात्रियों को असुविधा होती थी। अकेले यात्री को भी रिक्शा-टैक्सी के लिए तीन गुना किराया देना पड़ता था। अब ई-बाइक टैक्सी के माध्यम से आम यात्रियों की यह असुविधा दूर हो जाएगी।'

सरनाईक ने यह भी बताया कि, 'महाराष्ट्र में ई-बाइक टैक्सियों को अनुमति देने का निर्णय पूरे महाराष्ट्र में लिया गया है। इसके लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। एक संगठन जो 50 बाइक एक साथ ले जाता है, उसे ऐसे यात्रियों को ले जाने की अनुमति दी जाएगी। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अच्छे नियम बनाए हैं। हम केवल दो यात्रियों के बीच विभाजन और मानसून के दौरान यात्रियों को भीगने से बचाने के लिए पूरी तरह से कवर वाली ई-बाइक को ही अनुमति देंगे। राज्य सरकार ने ई-बाइक को बढ़ावा देने के लिए यह नीति तय की है।'

यात्री किराया कितना होगा?

इस बीच, सरनाईक ने कहा कि इस ई-बाइक टैक्सी के यात्री किराए के संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'यात्री किराये के संबंध में जल्द ही निर्णय

लिया जाएगा। इस संबंध में निर्णय के लिए हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। नीति को आज मंजूरी दे दी गई है। हम यात्रियों को न्यूनतम दरों पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।'

प्रताप सरनाईक ने बताया, 'सरकार यात्री किराए को लेकर नियम बनाने जा रही है। हम योजना बना रहे हैं कि रिक्शा में 100 रुपये में जो यात्रा करनी पड़ती है, उसे ई-बाइक टैक्सी में 30 से 40 रुपये में कैसे पूरा किया जा सकता है। अगले एक-दो महीने में ई-टैक्सी बाइक शुरू हो जाएंगी।' उन्होंने कहा, 'हम रिक्शा निगम के सदस्य चालकों को 10,000 रुपये की सब्सिडी देने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में चर्चा हुई है। अगर किसी रिक्शा चालक का बेटा या बेटा ई-बाइक टैक्सी लेता है, तो सरकार उसे 10,000 रुपये की सब्सिडी देगी और बाकी रकम उन्हें लोन के रूप में लेनी चाहिए। ताकि बेटा या बेटा जेब में एक भी रुपया रखे बिना ई-बाइक टैक्सी ले सकें।' सरनाईक ने दावा किया, 'अकेले मुंबई महानगर क्षेत्र में 10,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। पूरे महाराष्ट्र में 20,000 नौकरियां पैदा होंगी।'



मूर्तिजापुर में गिरफ्तारी की आशंका से रेल्वे टीसी ने की आत्महत्या



मुर्तिजापुर (संवाददाता)। घरेलू कलह से व्यथित रेलवे टिकट निरीक्षक सुमेश मेथ्राम (40) ने 31 मार्च की रात झूठी के दौरान आत्महत्या कर ली। उन्होंने तेज रफ्तार मालगाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना से रेलवे प्रशासन, सहकर्मियों और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार, सुमेश मेथ्राम मुर्तिजापुर रेलवे स्टेशन पर तैनात थे। हाल ही में उनके खिलाफ घरेलू विवाद को लेकर पुलिस शिकायत दर्ज हुई थी। इसी मामले में मुर्तिजापुर शहर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी,

लेकिन झूठी पर होने के कारण उनकी गिरफ्तारी झूठी समाप्त होने के बाद की जानी थी। गिरफ्तारी की आशंका से मानसिक रूप से परेशान मेथ्राम ने रात 8.30 बजे के बीच प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर अपनी जान देने का कठोर कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस दुखद घटना से सहकर्मियों और रेलवे कर्मचारियों में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मेडिकलेम पॉलिसी से प्राप्त राशि चिकित्सा व्यय के मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता - बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई- बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मेडिकलेम पॉलिसी के तहत किसी व्यक्ति की ओर से प्राप्त राशि को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत चिकित्सा व्यय के लिए दावेदार को देय मुआवजे की राशि से नहीं काटा जा सकता है। जस्टिस एस चंद्रकर, जस्टिस मिलिंद जाधव व जस्टिस गौरी गोडसे की पूर्ण पीठ ने 28 मार्च को फैसले में कहा कि मेडिकलेम पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि दावेदार की ओर से बीमा कंपनी के साथ किए गए अनुबंध के मद्देनजर प्राप्त की जाती है। इसलिए मेडिकलेम पॉलिसी के तहत दावेदार की ओर से प्राप्त किसी भी राशि की कटौती पूर्ण पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों दावा न्यायाधिकरण को न सिर्फ का हवाला देते हुए कहा कि मोटर दुर्घटना उचित

मुआवजा देने का अधिकार है, बल्कि यह उसका कर्तव्य भी है। प्रीमियम का भुगतान करने के बाद, यह स्पष्ट था कि लाभकारी राशि या तो पॉलिसी की परिपक्वता पर या मृत्यु पर, चाहे मृत्यु का तरीका कुछ भी हो, दावेदार के हिस्से में आएगी। अदालत ने कहा, उल्लंघनकर्ता मृतक की दूरदर्शिता और बुद्धिमानी से किए गए वित्तीय निवेश का फायदा नहीं उठा सकता। यह कानून की स्थापित स्थिति है। बीमा कंपनी ने दावा किया कि मेडिकलेम पॉलिसी के तहत प्राप्त बीमा राशि में चिकित्सा व्यय भी शामिल है। कंपनी ने कहा कि यह दोगुना मुआवजा होगा। स्वीकार्य नहीं होगा। विभिन्न एकल व खंडपीठों के अलग-अलग विचार रखने के बाद इस मुद्दे को पूर्ण पीठ के पास भेज दिया गया था।

सतारा जिले में चीनी उत्पादन में 19 लाख रुपये की गिरावट

मुम्ना मुजावर
सतारा: जिले में मिलों का चालू गन्ना पेरार्डि सत्र समाप्त हो गया है और जिले में 17 मिलों द्वारा 94 लाख 31 हजार 288 टन गन्ने की पेरार्डि की गई है, जिसमें नौ सहकारी और आठ निजी मिलें शामिल हैं। पुणे चीनी आयुक्तालय ने बताया है कि जिले में 91 लाख 50 हजार 27 क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है, जिसकी औसत उपज 9.70 प्रतिशत है। पिछले साल



2023-24 का फसल सीजन 6 अप्रैल तक चला था। उस सीजन में जिले में 105,23,881 टन गन्ने की पेरार्डि की गई थी और 10.49 प्रतिशत चीनी की उपज के साथ 110,34,568 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया था। इस वर्ष जिले में चीनी उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 18 लाख 84 हजार 541 क्विंटल कम हुआ है। कुछ अपवादों को छोड़कर, जर्देश्वर (गुरु कम्पोजिट), एक निजी कारखाना जो शुरू से ही प्रथम स्थान पर रहा है, ने गन्ना पेरार्डि में अपनी बढ़त बरकरार रखी है। कृष्या सहकारी शक्कर कारखाना ने चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्पादन के मामले में रयात सहकारी चीनी कारखाना 12.08 प्रतिशत उत्पादन के साथ अग्रणी रहा

जिले में सहकारी चीनी मिलों ने 44,83,455 टन गन्ने की पेरार्डि करके 11.50 प्रतिशत की औसत उपज पर 51,56,942 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है, जबकि निजी मिलों ने 49,47,833 टन गन्ने की पेरार्डि करके 8.07 प्रतिशत की औसत उपज पर 39,93,085 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है।

पिछले वर्ष गन्ना उगाने वाले किसानों को गन्ने का 100 रुपये प्रति टन अधिक मूल्य दिया गया था। साथ ही, पिछले कई वर्षों से किसानों के पंजीकृत क्षेत्र में एक भी गन्ना पेरार्डि से अछूता न रहे, इसके लिए अनुकरणीय कार्यवाही कर रही अजिंक्यतारा फेडरी ने समय पर सभी पंजीकृत क्षेत्रों में गन्ने की पेरार्डि पूरी कर ली है। इस आगामी सत्र में भी आदर्श कार्य पद्धति को सखी से लागू किया जाएगा। -जीवाजी मोहिते, कार्यकारी निदेशक, अजिंक्यतारा सहकारी शक्कर कारखाना

रास नहीं आई हरकत



पैराजि को बड़े ही गुरु से पोज देनेवाले सलमान कलाकारों को बड़े ही गुरु से पोज देनेवाले सलमान को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाले फैंस अकसर राशिका को अपना हाथ देकर बाहर अपने पसंदीदा कलाकारों की छोटी से छोटी निकलने में मदद करने की बजाय बातों पर नजर रखते हैं। अपने मनपसंद उन्हें खींचते हुए बाहर निकालते हैं, कलाकार की बात या हरकत पसंद न आने जिससे उनका संतुलन गड़बड़ा जाता पर वो उन्हें खरी-खोटी सुनाने से भी बाज है। किसी तरह खुद को संभालने नहीं आते। सोशल मीडिया पर एक ऐसा के बाद सलमान के साथ ही वीडियो वायरल हो रहा है, पोज देनेवाली जिसमें एयरपोर्ट पर स्पोर्ट राशिका के इस वीडियो को देखने हुए सलमान खान अपनी को देखने के बाद एक यूजर 'सिकंदर' को-स्टार राशिका के इस वीडियो ने लिखा, 'यह मंदाणा का हाथ पकड़कर, 'यह कटौती पूर्ण पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों दावा न्यायाधिकरण उन्हें गाड़ी से खींचते हुए बाहर निकाल रहे हैं। वीडियो में क्या बदतमीजी है।' दूसरे ने लिखा, 'पुष्पा किधर है तू।' एक ने लिखा, 'इसीलिए हीरोइनें इसके साथ काम नहीं करती।'

माही के घुटने ने दिया जवाब

एमएस धोनी को पिछले दिनों अपने बैटिंग क्रम के कारण खूब ट्रोल होना पड़ा है। पिछले मैच में नौवें क्रम पर बैटिंग करने आए थे, जिसे सीएसके की हार का मुख्य कारण बताया गया था, वहीं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में धोनी सातवें क्रम पर बैटिंग करने आए, लेकिन टीम को 6 रनों की हार से नहीं बचा पाए। धोनी पिछले सीजन भी निरंतर 7-8 नंबर पर बैटिंग करते देखे गए थे। बैटिंग क्रम को लेकर हो रही आलोचनाओं के बीच टीम के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा

कि माही के घुटने अब जवाब देने लगे हैं और उनके लिए निरंतर 10 ओवरों तक बैटिंग कर पाना संभव नहीं है। यह



उनके निचले क्रम पर बैटिंग करने का एक मुख्य कारण है। धोनी की उम्र 43 वर्ष हो गई है और बैटिंग के समय बहुत कम गेंद खेलते हैं।

अमर बाबासाहेब अधर में ल के तहत इ ठप पड़ा है आरोप ल है। अब ज बड़ा सवाल पाएगा? स लईमोईम स्मारकी कहां विभास स्मारकी काई को चेन्निसि लिहैं। मजबू नाराजगी बढ़ के नाम पर उ सुस्त कार्यो में देरी हो र मामले में अ

